

‘100 प्रतिशत आटा’ दावे पर आशीर्वाद आटे को राहत लाइसेंस रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक

एफएसएसएआई की कार्रवाई के खिलाफ आईटीसी की याचिका पर 9 सितंबर को अगली सुनवाई

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आईटीसी लिमिटेड के आशीर्वाद एमपी चक्की आटा के फूड बिजनेस लाइसेंस को रद्द करने के भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि फिलहाल एफएसएसएआई कंपनी के लाइसेंस के

खिलाफ कोई अंतिम कार्रवाई नहीं कर सकेगा। मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।

यह विवाद आशीर्वाद आटे की पैकिंग और प्रचार सामग्री में इस्तेमाल किए गए ‘100 प्रतिशत आटा’, ‘100 प्रतिशत मध्य प्रदेश गेहूं’ और ‘0 प्रतिशत मैदा’ जैसे दावों से जुड़ा है।



खास-खाबरें

स्मार्टफोन रखने की जगह बन सकती है खतरा, गलत पॉकेट में रखने से हो सकता है नुकसान

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: स्मार्टफोन आज लोगों की जरूरत बन चुका है, लेकिन इसे रखने और इस्तेमाल करने में लापरवाही नुकसानदायक साबित हो सकती है। कई मामलों में स्मार्टफोन की बैटरी में खराबी, ज्यादा गर्मी या तकनीकी समस्या के कारण ब्लास्ट होने की घटनाएं सामने आती हैं। इससे लोगों को चोट लगने के साथ कपड़ों और अन्य सामान को भी नुकसान पहुंच सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार स्मार्टफोन को ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहां उस पर लगातार दबाव पड़े या गर्मी बढ़ने की संभावना हो। खासतौर पर पैंट की पिछली जेब में फोन रखने से बचना चाहिए, क्योंकि बैठने के दौरान फोन पर दबाव पड़ सकता है और बैटरी को नुकसान पहुंच सकता है।

स्मार्टफोन को शरीर से चिपकाकर लंबे समय तक रखने से भी गर्मी बढ़ सकती है। यदि फोन इस्तेमाल के दौरान बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, बैटरी तेजी से खत्म हो रही है या फोन का पिछला हिस्सा फूलने लगा है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

मोबाइल फोन में लगी लिथियम आयन बैटरी अधिक गर्म होने, खराब चार्ज के इस्तेमाल या बैटरी में तकनीकी खराबी के कारण ज्वोलिम पैदा कर सकती है। इसलिए हमेशा कंपनी द्वारा प्रमाणित चार्जर और अच्छी गुणवत्ता वाली एक्सेसरीज का इस्तेमाल करना चाहिए। सुरक्षा के लिए फोन को खुले और सुरक्षित स्थान पर रखना बेहतर होता है। चार्जिंग के दौरान फोन को तर्किए, कंबल या बंद जगह पर रखने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और खतरा बढ़ सकता है।

महाराष्ट्र के नासिक से 800 टन प्याज लेकर बुधवार को दिल्ली पहुंचेगी ‘कांदा एक्सप्रेस’
नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाया है। महाराष्ट्र के नासिक से 800 टन प्याज लेकर पहली ‘कांदा एक्सप्रेस’ बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी नई पहुंचेगी। दिल्ली में 35 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी वाली दर पर प्याज को बेचा जाएगा। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने बताया कि दिल्ली में प्याज की खुदरा बिक्री नाफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के स्टोर के जरिये की जाएगी। उन्होंने बताया कि चार अन्य केंद्रों-चेन्नई, एर्नाकुलम, मदुरै और गुवाहाटी के लिए समर्पित रेलवे रैक के जरिए कांदा एक्सप्रेस से थोक प्याज भेजा जा रहा है। इन केंद्रों के लिए भेजा जा रहा प्याज महाराष्ट्र के नासिक में रखे गए बफर स्टॉक का हिस्सा है। खरे ने बताया कि प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए इस स्टॉक को बाजार में उतारा जा रहा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार 24 अगस्त को देश में प्याज की औसत खुदरा कीमत सालाना आधार पर 59 फीसदी बढ़कर 43.53 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, जबकि एक साल पहले यह 27.37 रुपये प्रति किलोग्राम थी। इसी तरह औसत थोक कीमत 68 फीसदी ढ़कर 35.58 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जो एक साल पहले 21.23 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

3400 किस वाले निशानों की वजह से चर्चा में आई कार, पुलिस ने की कार्रवाई

नईदुनिया ब्यूरो, ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक सफेद मारुति स्विफ्ट कार अपने अनोखे डिजाइन के कारण चर्चा में आ गई। कार पर बने 3400 से अधिक किस के निशान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने वाहन की जांच कर मोटर वाहन नियमों के तहत कदम उठाया।

जानकारी के अनुसार, कार के पूरे बाहरी हिस्से पर बड़ी संख्या में किस के निशान बनाए गए थे। इसी वजह से इसे ‘किसिंग कार’ कहा जाने लगा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यह कार लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि वाहन में किए गए बदलाव और डिजाइन को लेकर नियमों की जांच जरूरी है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहनों में किए जाने वाले कुछ बदलावों के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक होता है।

अधिकारियों के अनुसार, वाहन की सुरक्षा और नियमों के पालन को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई। पुलिस ने वाहन से जुड़े दस्तावेज और किए गए बदलावों की जानकारी ली। वाहनों को आकर्षक बनाने के लिए लोग अक्सर अलग-अलग तरह के डिजाइन और स्टिकर लगाते हैं, लेकिन किसी भी तरह के बदलाव से पहले नियमों का पालन करना जरूरी होता है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। किसिंग कार का मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा और मोटर वाहन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की जांच आगे भी जारी रहेगी।

गूगल ने हटाए तीन फर्जी लोन एप, डेटा चोरी और मनमाने ब्याज वसूली के आरोप

- ▶▶ **गृह मंत्रालय की शिकायत पर कार्रवाई**
- ▶▶ **अगस्त में अब तक नौ ठगी वाले एप बंद**
- ▶▶ **सरकार ने यूजर्स को सतर्क रहने की सलाह दी**

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: गृह मंत्रालय की शिकायत के बाद गूगल ने प्ले स्टोर से तीन फर्जी लोन एप हटा दिए हैं। इन एप्स पर लोगों की निजी जानकारी चोरी करने, कम ब्याज पर तुरंत लोन देने का झांसा देने और बाद में भारी ब्याज व पेनाल्टी वसूलने के आरोप लगे थे। अगस्त महीने में अब तक कुल नौ ऐसे फर्जी लोन एप्स पर कार्रवाई की जा चुकी है।

गृह मंत्रालय की साइबर सुरक्षा टीम इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने 19 अगस्त को गूगल को नोटिस भेजकर तीन एप्स को हटाने के लिए कहा था। इनमें होराइजन कैश सर्विस, मनी स्कोर

मॉनिटर और जेलीक्रेडिट शामिल हैं। आरोप है कि ये एप्स कुछ ही मिनटों में लोन देने का दावा कर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे।

एप डाउनलोड करने के बाद ये उपयोगकर्ताओं के फोन से कई निजी जानकारीयों तक पहुंच बना लेते थे। इनमें पहचान से जुड़े दस्तावेज, बैंक खाते की जानकारी, संपर्क सूची, फोटो गैलरी और कैमरे का एक्सेस शामिल था। टग इस जानकारी का इस्तेमाल लोगों को परेशान करने और ब्लैकमेल करने के लिए करते थे।

सरकारी नोटिस मिलने के कुछ घंटों के भीतर गूगल ने इन एप्स को

प्ले स्टोर से हटा दिया। यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधानों के तहत की गई है। इससे पहले 7 अगस्त को भी सरकार ने छह फर्जी लोन एप्स को हटाने के निर्देश दिए थे। इनमें लोन ऑर्बिट, हिसाब, नेक्स लोन, वन फंड, क्रेडिट फैक्टर और मोबाइल क्रेडिट शामिल थे।

फर्जी लोन एप्स अक्सर सोशल मीडिया और ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को आकर्षित करते हैं। इनमें बिना दस्तावेज और बिना सबिल स्कोर के तुरंत बड़ी रकम का लोन देने का दावा किया जाता है। जरूरतमंद लोग इन विज्ञापनों के

झांसे में आकर एप डाउनलोड कर लेते हैं। सरकार ने लोन एप्स के अलावा फर्जी वेबसाइट्स पर भी कार्रवाई की है। इसी महीने गूगल के फायरबेस सर्वर पर चल रही करीब 57 संदिग्ध वेबसाइट्स और डेटाबेस को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ऑनलाइन लोन लेने से पहले यह जांचना जरूरी है कि एप किसी पंजीकृत बैंक या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से जुड़ा है या नहीं। उपयोगकर्ताओं को भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर कंपनी की जानकारी सत्यापित करनी चाहिए। लोन एप अगर संपर्क सूची, फोटो गैलरी जैसी अनावश्यक 12 अनुमति मांगे या लोन देने से पहले शुल्क की मांग करे तो सावधान रहना चाहिए। किसी अनजान लिंक या एपीके फाइल से एप डाउनलोड नहीं करना चाहिए। फर्जी एप से परेशानी होने पर राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है और संबंधित साइबर सेल से संपर्क किया जा सकता है।

बच्चे के भविष्य हेतु पीपीएफ में करें निवेश 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं बचत

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: बच्चों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए माता-पिता पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी पीपीएफ खाते में निवेश कर सकते हैं। इस योजना में वर्तमान में 7.1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जा रहा है। बच्चे के नाम पर पीपीएफ खाता खोलकर लंबी अवधि में लाखों रुपये का फंड तैयार किया जा सकता है।

नाबालिग बच्चे का पीपीएफ खाता केवल माता-पिता या कानूनी अभिभावक ही खोल और संचालित कर सकते हैं। नियमों के अनुसार एक व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक पीपीएफ खाता खोल सकता है। इसके अलावा वह अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर एक अतिरिक्त खाता खोल सकता है। यदि किसी व्यक्ति के दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के नाम पर पीपीएफ खाता खोलने के लिए अलग-अलग अभिभावक की जरूरत होगी। ऐसे मामलों में एक बच्चे का खाता मां और दूसरे बच्चे का खाता पिता खोल सकते हैं।

पीपीएफ खाते में जमा राशि की भी एक सीमा तय है। नाबालिग बच्चे के खाते में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि माता-पिता का खुद का पीपीएफ खाता



ही है तो उनके खाते और बच्चे के खाते में जमा कुल राशि मिलाकर सालाना सीमा 1.5 लाख रुपये ही होगी।

उदाहरण के तौर पर यदि कोई अभिभावक अपने पीपीएफ खाते में एक लाख रुपये और बच्चे के खाते में 80 हजार रुपये जमा करता है तो कुल राशि एक लाख 80 हजार रुपये हो जाएगी। लेकिन नियमों के अनुसार केवल एक लाख 50 हजार रुपये तक की जमा राशि ही मान्य होगी। अतिरिक्त 30 हजार रुपये पर पीपीएफ ब्याज और कर लाभ नहीं मिलेगा।

बच्चे के 18 वर्ष का होने के बाद पीपीएफ खाते का दर्जा नाबालिग से बालिग में बदलने के लिए आवेदन करना होता है। इसके बाद खाताधारक खुद अपने खाते का संचालन कर सकता है। पीपीएफ खाते की परिपक्वता अवधि 15 वर्ष होती है। अवधि पूरी होने के बाद खाताधारक पूरी राशि निकाल सकता है।

टीवीएस आईक्यूब की 10 लाख यूनिट बिक्री का जश्न, 145 किमी रेंज वाला खास संस्करण लॉन्च

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: टीवीएस मोटर ने अपने लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटर आईक्यूब की 10 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। इस उपलब्धि के बाद कंपनी ने आईक्यूब का विशेष संस्करण लॉन्च किया है। नए संस्करण में बेहतर रेंज और आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं।

कंपनी के अनुसार, टीवीएस आईक्यूब का यह खास मॉडल एक बार चार्ज करने पर करीब 145

किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में बढ़ती मांग के बीच कंपनी ने इस संस्करण को ग्राहकों के लिए पेश किया है। टीवीएस आईक्यूब को भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर श्रेणी में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। इसकी बिक्री का 10 लाख यूनिट तक पहुंचना कंपनी के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। नए विशेष संस्करण में डिजाइन और

वैश्विक स्तर पर बढ़ा यूपीआई का दायरा, 11 देशों में पहुंचा भारत का डिजिटल भुगतान सिस्टम

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई अब केवल घरेलू डिजिटल भुगतान व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा है। भारतीय भुगतान प्रणाली का विस्तार लगातार बढ़ रहा है और अब यह 11 देशों तक पहुंच चुकी है। हाल ही में ग्रीस और मालदीव के जुड़ने के बाद विदेशों में यूपीआई की स्वीकार्यता और बढ़ गई है। यूपीआई ने भारत में डिजिटल लेनदेन को आसान और तेज बनाया है। अब यही तकनीक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही है। कई देश भारतीय डिजिटल भुगतान मॉडल को अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं, जिससे भारत की डिजिटल ब्याज और कर लाभ नहीं मिलेगा।

यूपीआई के जरिए उपयोगकर्ता मोबाइल फोन से तुरंत भुगतान कर सकते हैं। इसकी तेज, सुरक्षित और सरल होती है। यही कारण है कि दूसरे देश भी इस तकनीक को अपने भुगतान तंत्र में शामिल कर रहे हैं। विदेशों में यूपीआई की मौजूदगी से भारतीय यात्रियों को भी सुविधा मिल रही है।

स्पेशल खबर जापानी निवेशकों को भरोसा, भारत में डेटा सुरक्षा और तकनीक की सुरक्षा की गारंटी

भारत में सफल होने पर कोई अचानक गायब नहीं होता: गोयल

टोक्यो, एजेंसी: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चीन का नाम लिए बिना उस पर तंज कसा है। टोक्यो में सुमितोमो कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ बैठक के दौरान गोयल ने जापानी निवेशकों को भारत में कारोबार के सुरक्षित माहौल का भरोसा दिलाया। गोयल ने कहा कि भारत में उद्यमिता का सम्मान किया जाता है। यहां किसी कारोबारी को इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती कि सफल होने या पैसा कमाने के बाद वह अचानक गायब हो जाएगा और बाद में किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनकर सामने आएगा।

गोयल का यह बयान चीन के कारोबारी जैक मा के मामले की ओर इशारा माना जा रहा है। जैक मा वर्ष



2020 में चीन के वित्तीय नियामकों की आलोचना के बाद कई महीनों तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहे थे। इसके बाद उनकी कंपनी एंट ग्रुप के प्रस्तावित आईपीओ को रद्द कर दिया

गया था और अलीबाबा पर भारी जुर्माना लगाया गया था। वर्ष 2023 में जैक मा टोक्यो विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में सामने आए थे।

आईटीसी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा

एफएसएसएआई का कहना है कि ‘100 प्रतिशत’ जैसे दावों का उपयोग उसकी मई 2025 की एडवाइजरी के नियमों के अनुरूप नहीं है और इससे उपभोक्ताओं में भ्रम पैदा हो सकता है।

एफएसएसएआई ने 10 अगस्त को आईटीसी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके बाद 13 अगस्त को सुधार नोटिस जारी किया गया और कंपनी को 15 दिन में अनुपालन करने का निर्देश दिया गया। आईटीसी ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

आईटीसी की ओर से अदालत में तर्क दिया गया कि कारण बताओ नोटिस के लिए 30 दिन का समय दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही सुधार नोटिस जारी कर दिया गया। कंपनी ने यह भी कहा कि एफएसएसएआई केवल एडवाइजरी के आधार पर बाध्यकारी प्रतिबंध लागू नहीं कर सकता। आईटीसी ने यह तर्क भी दिया कि एफएसएसएआई ने उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर कोई आरोप नहीं लगाया है। वहीं, एफएसएसएआई ने याचिका की सुनवाई को लेकर दिल्ली

हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया। प्राधिकरण ने कहा कि सुधार नोटिस कोलकाता स्थित क्षेत्रीय प्राधिकरण की ओर से जारी किया गया था और कंपनी को पहले खाद्य सुरक्षा आयुक्त के समक्ष अपील करनी चाहिए थी। हाईकोर्ट ने कहा कि पहले यह तय किया जाएगा कि याचिका पर सुनवाई का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र उसके पास है या नहीं। अदालत ने दोनों पक्षों से इस मुद्दे पर संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा है। तब तक एफएसएसएआई लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई नहीं कर सकेगा।

एआई शिक्षा के बहाने अमेरिकी स्कूलों में बढ़ रहा टेक कंपनियों का प्रभाव

न्यूयॉर्क, एजेंसी: अमेरिका के स्कूलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते इस्तेमाल के साथ बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों का प्रभाव भी तेजी से बढ़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एपल और ओपनएआई जैसी कंपनियां छात्रों और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और तकनीकी उपकरण उपलब्ध करा रही हैं। हालांकि, इनके बढ़ते हस्तक्षेप को लेकर कई जगहों पर विरोध भी शुरू हो गया है।

अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर्स ने माइक्रोसॉफ्ट और ओपनएआई के साथ मिलकर 220 करोड़ रुपये से अधिक का कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। समर्थकों का कहना है कि इससे छात्रों को आधुनिक तकनीक सीखने में मदद मिलेगी, जबकि आलोचकों का मानना ​​है कि इससे शिक्षा व्यवस्था पर कॉर्पोरेट हितों का प्रभाव बढ़ सकता है और शिक्षकों की भूमिका कमजोर हो सकती है।

टेक कंपनियां स्कूलों को लैपटॉप, टैबलेट, ऑपरेटिंग सिस्टम और शैक्षणिक एप उपलब्ध करा रही हैं। इसके साथ

ही वे अपने अनुकूल तकनीकी विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी पैवो करती हैं। माइक्रोसॉफ्ट अपने माइनक्राफ्ट गेम के माध्यम से कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा उपलब्ध कराता है।

लॉस एंजेलिस यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट जैसे बड़े स्कूल सिस्टम ने विरोध के बीच छोटे बच्चों के लिए आईपैड और क्रोमबुक के इस्तेमाल को सीमित करने का फैसला किया है। करीब एक दशक पहले टेक कंपनियां स्कूलों में कोडिंग शिक्षा को बढ़ावा दे रही थीं, लेकिन अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विस्तार के साथ उनका ध्यान एआई शिक्षा पर केन्द्रित हो गया है।

कुछ शिक्षकों और प्रोफेसरों ने चिंता जताई है कि एआई चैटबॉट छात्रों को प्रतिक्रिया देने जैसे शिक्षकों के महत्वपूर्ण कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैंड स्मिथ ने कहा कि सरकारी स्कूल अक्सर आधुनिक विषयों को पढ़ाने और बदलती बाजार जरूरतों के अनुसार छात्रों को तैयार करने में पीछे रह जाते हैं।

सैसेक्स में 287 अंकों की तेजी निफ्टी 24,335 के स्तर पर बंद



कोसपी सूचकांक 46 अंक बढ़कर 6,743 पर पहुंचा, जबकि जापान का निक्केई 328 अंकों की बढ़त के साथ 65,856 पर बंद हुआ। वहीं, हांगकांग का हेंगसेंग सूचकांक छह अंक की गिरावट के साथ 25,511 पर रहा।

इससे पहले 24 अगस्त को अमेरिकी बाजारों में भी मिला-जुला रुख देखने को मिला था। डाउ जोंस 140 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि नैसडेक और एसएंडपी 500 में गिरावट

रही। अन्ू प्रोजेक्ट्स का आईपीओ मंगलवार से खुल गया है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 175.06 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। निवेशक इसमें 28 अगस्त तक बोली लगा सकेंगे।

इसके अलावा ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड का आईपीओ 28 अगस्त को खुलेगा। कंपनी इसके माध्यम से 720 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। इसके लिए शेयर का मूल्य दायरा 408 रुपये से 429 रुपये तय किया गया है। निवेशक न्यूनतम 34 शेयरों के एक लॉट के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले निफ्टी 24 अगस्त को शेयर बाजार में गिरावट रही थी। सेंसेक्स 172 अंकों की गिरावट के साथ 77,369 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 33 अंक गिरकर 24,219 के स्तर पर पहुंच गया था।

रक्षाबंधन पर देशभर में 30 हजार करोड़ से ज्यादा का कारोबार होने की संभावना : खंडेलवाल

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: देशभर में रक्षाबंधन त्योहार के अवसर पर इस बार 30 हजार करोड़ रुपये का कारोबार होने की उम्मीद है। इसमें से अकेले राखी का कारोबार 25 हजार करोड़ रुपये का पहुंचने का अनुमान है। सांसद एवं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉफेंस में कहा कि रक्षाबंधन पर्व में अब केवल 4 दिन शेष रहने के साथ ही दिल्ली सहित देशभर के बाजारों में खरीदारी अपने चरम पर पहुंच गई है। दिल्ली के चांदनी चौक, सदर बाजार, करोल बाग, लाजपत नगर, कमला नगर, राजौरी गार्डन, गांधी नगर, खारी बावली, लक्ष्मी नगर तथा विभिन्न स्थानीय बाजारों में ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शाम के समय बाजारों में विशेष रौनक है और व्यापारियों के अनुसार इस वर्ष रक्षाबंधन का उत्साह पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक दिखाई दे रहा है।